जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोन:- 2418945 फैक्स:- 0294-2410146 वर्ष: 30 संख्या: 119 प्रभात उदयपुर, बुधवार 1 मार्च, 2023 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तब कई बार आप अपना अनुभव यह कहकर साझा करना चाहते हैं, ''अरे वाह जरा उधर देखो।'' हाल ही में एक शोध से पता चला है कि चिम्पैंज़ी भी ऐसा करते हैं। अब तक यही माना जाता था कि यह व्यवहार सिर्फ इंसानों में होता है, पर, वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अवयस्क मादा चिम्पैंज़ी को अपनी मां को एक पत्ती दिखाते हुए देखा, मानो वो मां से कह रही हो, ''देखो पत्ती कितनी अच्छी है।'' अपने शोध में वैज्ञानिकों ने इसे ''डिक्लरेटिव रैफरैन्शियल जैस्चरिंग'' की संज्ञा दी है। जिसका अर्थ है, बिना किसी उद्देश्य के कोई चीज दिखाना, सिर्फ इसलिए कि, दूसरा उसे देख ले। उन्होंने यह घटना युगांडा के किबाले नैशनल पार्क की एनगोबो चिम्प कम्युनिटी में देखी थी। शोध की सहलेखक केटी स्लोकोम्ब, जो यू.के. की युनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं, ने कहा ''महत्वपूर्ण बात यह है कि, चिम्पैंज़ी की बेटी, जिसका नाम फिओना है, अपनी मां से ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि वह पत्ती का कुछ करे, वह तो बस उसे पत्ती दिखाना चाहती थी, मानो कह रही हो, ''देखो-देखो यह कितनी अच्छी हैं, है ना?'' यह बिल्कुल इंसानी व्यवहार जैसा हैं। हम सोचते थे कि, यह सिर्फ इंसानों में ही मिलता है।'' चिम्पैंज़ी एक दूसरे को ''ग्रूम'' करते समय पेड़ों से पत्तियां तोड़ते हैं। आम धारणा है कि, एक दूसरे के शरीर से परजीवी कीट निकालते समय वो पत्ती का इस्तेमाल पैट्रीडिश (लैब में काम आने वाली कांच की कटोरी) की तरह करते हैं और उसमें कीट इकट्ठे करके उनका निरीक्षण करते हैं। स्लोकोम्ब ने कहा, जब फिओना अपनी मां को पत्ती दिखा रही थी तब उसकी मां की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर फिओना लगातार अपनी मां को पत्ती दिखाने की कोशिश करती रही और जब उसकी मां ने पत्ती की तरफ देख लिया, तब फिओना संतुष्ट नजर आई। यह शोध जंगल में या किसी भी अन्य जानवर में इस तरह के व्यवहार का पहला प्रमाण है। जो दिखाता है कि, चिम्पैंज़ी और शायद अन्य एप्स यह समझते हैं कि, दूसरे लोग भी वैसे ही जानकारी एकत्र करते हैं जैसे वो स्वयं करते हैं तथा इस जानकारी को वो साझा करना चाहते हैं।

15 साल पुराने केस में लालू यादव व उनके परिवार के खिलाफ सम्मन जारी

सी.बी.आई. ने एक बार 2021 में केस बंद करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि ठोस व पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। एक असामान्य संयोग के अन्तर्गत, सी.बी.आई., आर.जे.डी. प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ नये सिरे से हरकत मे आ गई है। सी.बी.आई. इस काम में ऐसे समय जुटी है, जब बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल सात मित्र दल अगले साल होने वाले संसदीय चुनावों में भाजपा को हराने की रणनीतियाँ बना रहे हैं।

- पर, गत अक्टूबर माह में सी.बी.आई. ने अचानक सक्रियता दिखाते हुए, एक नयी चार्जशीट पेश की, दिल्ली के कोर्ट में तथा न्यायालय ने लालू यादव, राबड़ी देवी सहित उनके परिवार के 14 सदस्यों को 15 मार्च को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये सम्मन जारी किये।
- मामला 2004-2009 के अंतराल का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे।
- उन पर आरोप लगाया गया है कि, उन्होंने व उनके परिवार ने रेलवे के मुम्बई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर व हाजीपुर ज़ोन में कई आवेदकों से उपहार के रूप में जमीन प्राप्त कर ग्रुप डी की नियुक्तियाँ प्रदान कीं।
- इसके अलावा, इस प्रकरण में लालू यादव के परिवार ने पटना में 1,05,292 वर्ग फुट भूमि प्राप्त की। सी.बी.आई. ने दावा किया है कि, उसके पास इसके सबूत हैं।
- इस समय, जब लालू यादव की पार्टी भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनाकर, 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, सी.बी.आई. का अचानक सक्रिय होना सामान्य बात नहीं लग रही।

सी.बी.आई. द्वारा ''लैंड फॉर जॉब्स'' घोटाले में आर.जे.डी. के इस शीर्ष परिवार के खिलाफ पेश की गई नई चार्ज शीट के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद तथा राबड़ी देवी एवं मीसा भारती सहित उनके 14 परिजनों के खिलाफ सम्मन जारी कर दिये हैं। दिल्ली के राउज़ अवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी करके, उनसे 15 मार्च को अदालत में उपस्थित होने के लिये कहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में पेश की गई एक चार्ज शीट में, सी.बी.आई. ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद 2004 से 2009 के बीच जब रेल मंत्री थे, तो रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों ने लालू प्रसाद तथा उनके परिजनों के उपहार में जमीन के विभिन्न पार्सल दिये थे।

प्रसंगवश बता दें कि ठोस साक्ष्यों के अभाव में, सी.बी.आई. ने 2021 में प्रसाद तथा उनके परिजनों के खिलाफ अपना यह केस बंद कर दिया था लेकिन इस जाँच एजेंसी ने गत वर्ष अक्टूबर में इस प्रकरण को फिर से खोल लिया। इस केस को फिर से खोले जाने से पहले, सी.बी.आई. ने गत वर्ष जुलाई में प्रसाद के मुख्य सहायक मोला यादव को गिरफ्तार कर लिया था। मोला यादव प्रसाद के रेल-मंत्रित्वकाल में उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हुआ करते थे। अपनी एफ.आई.आर. में, सी.बी.आई. ने आरोप लगाया था कि बहुत से लोगों को रेलवे के विभिन्न ज़ोनों- मुम्बई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर तथा हाजीपुर में ग्रुप डी की नौकरियाँ दी गई थीं। इन नौकरियों के बदले में, नौकरी चाहने वालों ने कथित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब के राज्यपाल व मु.मंत्री की खूब ठनी वि.सभा सत्र के मुद्दे पर

मु.मंत्री ने तीन मार्च से विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिये राज्यपाल को पत्र लिखा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को सुप्रीम कोई का दरवाजा खटखटाया। खींचतान का कारण यह रहा कि राज्यपाल ने आगामी 3 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने से इन्कार कर दिया था।

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी चीफ जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की एक बैंच के समक्ष मान का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे त्वरित सुनवाई के लिए बाध्य किया। हालांकि यह मुद्दा तब बेअसर हो गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बैंच को बताया कि राज्यपाल सत्र की शुरूआत 3 मार्च से करने पर सहमत हो गए हैं।

- राज्यपाल ने कहा कि, सत्र आहूत करने से पहले, वे कानूनी राय लेना चाहते हैं, अपमानजनक व आपत्तिजनक टिप्पणियों के बारे में, जो मु.मंत्री ने की हैं।
- मु.मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की, इस मुद्दे पर।
- पर अन्ततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सुनवायी के ठीक पहले राज्यपाल ने सत्र आहूत करने का निर्णय ले लिया।

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बैंच में इस मामले को मैंशन किया और इस पर त्वरित सुनवाई किए जाने की मांग की।

सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल का कहना है कि, चूंकि मुख्यमंत्री ने असंदर्भित मसलों पर कुछ टिप्पणियां की है, इसलिए वे सत्र आहूत नहीं फरेंगे। शीर्ष अदालत ने इसके बाद मामले को मंगलवार को ही दोपहर 3:50 बजे सुनवाई के लिए नियत कर लिया। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिखे गए ''अपमानजनक एवं स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ट्वीट्स व पत्र'' पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जो दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के सिलसिले में रविवार को

- सी.बी.आई. द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से मना कर दिया और कहा, पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाइए।

सी.बी.आई. द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया से कहा कि वे जमानत के लिये उच्च न्यायालय जायें।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़ इस केस की सुनवाई करना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना के भाजपा नेताओं को दिल्ली बुलाया हाई कमान ने

तेलंगाना के चुनाव की रणनीति व कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। भाजपा की तेलंगाना योजना की विस्तृत रूपरेखा के अनुसार भाजपा का सारा फोकस राज्य के भ्रष्टाचार व कुशासन पर हमले का रहेगा। मंगलवार तेलंगाना के स्थानीय नेताओं के बयानों तथा पार्टी के हैदराबाद के नेताओं तथा शीर्ष केन्द्रीय नेतृत्व- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा- की बैठक से यह बात उभर कर आई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव चुनाव निर्धारित समय से पहले करा सकते हैं। पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने तेलंगाना के पार्टी नेताओं से कहा है कि वे जमीनी स्थिति की गहन समीक्षा करें तथा विधानसभा चुनावों के लिये पार्टी की रणनीति तैयार करें।

मंगलवार को दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण मीटिंग के लिये आवश्यक जानकारी देने वाले नेताओं में शामिल हैं- तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष बन्डी

- बैठक बुलाने में इतनी तत्परता इसलिये दिखायी गयी, क्योंकि काफी चर्चा है कि, मु.मंत्री चन्द्रशेखर राव समय से पहले चुनाव करवाने की तैयारी कर रहे हैं।
- बहरहाल भाजपा को दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद, तेलंगाना से अच्छे नतीजों की आशा है चुनाव में।
- भाजपा की रणनीति के अनुसार पार्टी तेलंगाना में मु.मंत्री व उनके परिवार के वित्तीय घोटालों पर आक्रामक रूख रखेगी।
- जैसी कि चर्चा में है, मु.मंत्री की पुत्री कविता की कुछ भूमिका है, दिल्ली सरकार के ''लिकर काण्ड'' में।

संजय, राज्य-प्रभारी तरुण चुग, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, निज़ामाबाद सांसद अरविन्द धरमपुरी, सुधाकर रेड्डी- तमिलनाडु के सह-प्रभारी, के. लक्ष्मण तथा केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी। मीटिंग में उभर कर आई एक बड़ी सर्वसम्मत राय यह थी कि पार्टी मुख्यमंत्री के परिवार को निशाना बनायेगी तथा उसे दिल्ली के शराब-घोटाले से जोड़ेगी, जिसमें के.सी.आर. की पुत्री का एक सहयोगी गिरफ्तार हो चुका है।

हैदराबाद में धीमे स्वरों में ऐसी चर्चा है कि कविता भी गिरफ्तार हो सकती है। इस चर्चा को फैलाने वाले भाजपा के छुटभइये पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं। सूत्रों ने कहा कि ई.डी. की चार्जशीट के अनुसार, कविता के नाम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में नैटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि जयपुर व राजस्थान के अन्य जिलों में राजस्थान डायरैक्ट स्कूल

- राजस्थान में जयपुर व अन्य जिलों, जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है, में इन्टरनैट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में गाइड लाइन्स बनाए।

टीचर रिक्रूटमैन्ट एग्ज़ाम में इंटरनैट सेवाओं को हाल ही निलम्बित किये जाने को लेकर इंटरनैट शट डाउन के व्यावहारिक क्रियान्वयन की गाइडलाइन्स को लागू किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान ने नगण्य प्रगति की, ''एंटी टैररिस्ट'' गतिविधियों को रोकने के प्रयास में

अमेरिका के विदेश मंत्रालय को हर साल उन चुनिंदा देशों की, (जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है) इस संदर्भ में किये गये प्रयासों के बारे में एक रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। पाकिस्तान द्वारा आतंकी संगठनों पर किए गए वायदे पर कोई खास प्रगति नही करने के लिए अमेरिका ने उसकी भर्त्सना की है। पाकिस्तान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने देश में मौजूद सभी आतंकवादी संगठनों का बिना किसी विलम्ब और भेदभाव के सफाया कर देगा। यह जानकारी यू.एस. ब्यूरो ऑफ काउन्टर टैररिज़्म की ''कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टैररिज़्म 2021: पाकिस्तान'' में दी गई है।

अमेरिका के कानून के अनुसार विदेश मंत्री को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें आतंकवाद को लेकर उन देशों और ग्रुप्स की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिन्होंने विधान में तय मापदण्ड को पूरा किया है या नहीं।

- 2021 में आतंकवाद की स्थिति पर पेश रिपोर्ट में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि, पाकिस्तान ने लिखित में वादा किया था कि, बिना किसी विलम्ब के आतंकवादी संगठनों के ठिकानों व शिविरों को खत्म कर देगा। पर, इस वादे की पूर्ति की दिशा में नगण्य प्रगति हुई है।
- पाकिस्तान में वर्ष 2020 की तुलना में सन् 2021 में ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुईं।

पाकिस्तान में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में आतंकवादी गतिविधियां अधिक रहीं, जिसमें हमलों और मृतकों का आंकड़ा काफी अधिक रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल प्रमुख गुटों में तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टी.टी.पी.), बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बी.एल.ए. और आई.एस.आई.एस के शमिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने वर्ष 2015 के नैशनल एक्शन प्लान (एन.ए.पी.) की पुनर्समीक्षा की और इसे 20 पॉइन्ट प्लान से घटाकर ''14 की पॉइन्टस'' पर केन्द्रित कर दिया, लेकिन उसने प्रमुख पहलुओं पर बहुत ही कम प्रगति की है, खासतौर पर अपने इस प्रण पर कि वह सभी आतंकवादी संगठनों का बिना किसी विलम्ब और भेदभाव के सफाया कर देगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में अलगाववादी उग्रवादी गुटों द्वारा विभिन्न चुनिंदा ठिकानों पर आतंकवादी हमले किए गए। आतंकवादियों ने इन हमलों में कई तरकीबों का इस्तेमाल किया, जिसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जम्मू को डोगरास्तान बनाया जाए'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। अंकित लव (39), जो स्व. भीम सिंह द्वारा बनाई गई जम्मू-कश्मीर नैशनल पैंथर

- पैंथर्स पार्टी के मुख्य संरक्षक अंकित लव ने मांग की है कि, जम्मू को डोगरास्तान के रूप में भारत का 29वां राज्य घोषित किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत को लीडरशिप पुरस्कार

नयी दिल्ली, 28 फरवरी। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, बार्सिलोना में चल रहे वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस (डब्ल्यूएमसी) में भारत को टेलीकॉम क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गर्वमेंट लीडरशिप पुरस्कार मिला है, जो गौरव की बात है।

वैष्णव ने डब्ल्यूएमसी में जीएसएमए द्वारा भारत को गर्वमेंट लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर मंगलवार को संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र को यह पुरस्कार मिला है जो गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि, इस पुरस्कार की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि एक लंबे समय तक जिस तरह के टेलीकॉम सेक्टर में लगातार मसले बने रहते थे, कई तरह के कानूनी मुद्दे थे और कई तरह के अन्य मुद्दे थे, वे सब अब पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि, इस सैक्टर में प्रधानमंत्री मोदी ने कई तरह के सुधार किए हैं।